एकता या शोषण

आप इनमें से किसको चुनेगें? मैं यहाँ TV सीरियल लेखिका निर्देशिका एकता कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ जो परिवार तक मे एकता की बात नहीं करती। मैं राष्ट्र में एकता की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

कृपया शिकायतें कम करें ओर संगठन से एकता बढायें । ब्रिटिश राज के दौरान नेता जी केवल एक वाक्य लिख कर ICS की परीक्षा मे प्रथम आ गये थे, बह वाक्य था- विभाजित करो ओर राज्य करो । इसी मंत्र पर अब भी हमारी राजनीति चल रही है । इसका उल्टा हम कर पायें यानि एकता लाओ और शोषण बन्द करो तभी गाँधी जी का स्वराज्य बन सकेगा । एकता होगी तो जनता को सरकार से ज्यादा सेवायें मिलेगीं ओर कोई तुम पर राज नहीं कर सकेगा ।

यहाँ पर एक बात ध्यान से देखें तो पायेगे कि IAS IPS IFS IRS इत्यादि की नौकरियाँ क्यों इतनी लोकप्रिय हैं, क्योकि इस तबके के लोग जानतें हैं कि वे अपनी पद-शक्ति के प्रयोग से जनता को विभाजित करके आज भी स्वतंत्र कहलाने वाले भारत में अपना उल्लू सीधा कर सकतें हैं, जैसा विदेशी शासक करते थे । आप खुद ही अन्दाज लगा लीजिये। तीस राज्य बना दिये, जिलों DM के अलावा CEO बना दिये, पर क्या जनता की सेवाओं मे सुधार हुआ ? हाँ सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी ज़रूर हो गई है । पहले जब भारत आजाद हुआ था सिर्फ एक हजार ICS व IAS अधिकारी थे, आबादी तीस करोड़ थी पर अब आवादी एक सौ दो करोड़ हो गई मगर इन अधिकारियों की संख्या करीब चौदह हजार यानि चौदह गुनी क्यों हो गई जबकि हम सब जानते हैं - छोटी सरकार, सुखी संसार । यह सब इसलिये हुआ क्योंकि जनता बटी हुई है और अधिकारियों मे एकता है । ये सब लोग नेताओं के साथ मिलकर जनता को बेबकूफ बना रहें हैं, यह किसी व्यक्ति पर अरोप नहीं है, जिस तंत्र के अन्तर्गत यह सब हो रहा है उससे कुछ और अपेक्षा की भी नही जा सकती है । इनके इष्ट तो राज करने के लिये यह तंत्र बना गये थे। इन अफसरों की तनखा, पेन्शन, मेडीकल, प्रोविडेन्ट फंड, घर, पानी, बिजली आदि मिलाकर दस से बारह लाख रुपये हर साल प्रति अफसर खर्च होते हैं और जो अफसर रिश्वत लेते हैं उससे जनता के सरकारी कोष मे कटौती होती है सो अलग । भारतीय प्रेस व यू एन ओ की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 21060 रु प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार के सहारे प्रशासनिक वैधानिक व न्यायिक संस्थानो से संलग्न व्यक्तियों की जेबों में चले जाते हैं । जरा सोचिये इस राशि से जनता के भले के लिये कितने काम हो सकते हैं। इस लूट को रोकने के लिये जनता मे चेतना व एकता दोनो चाहिये । हमारा तंत्र ही ऐसा है कि इन पदों पर बैठे व्यक्ति चाह कर भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो तंत्र जनता को चूसने के लिये 1857 के गदर के बाद खुदगर्जी व बदला लेने की भावना से बनाया गया था वह देश का भला हरगिज नहीं कर सकता । स्वतंत्रता के बाद भी हमने उस तंत्र को न तो बदला है ना हमारे संविधान में इसको बदलने का कोई प्राविधान ही है । अंग्रेजों को जी हजूरी करने वाले चाटुकार भारतीय आधिकारियो की जरुरत थी न कि जनता के सच्चे सेवको की । उन्हें जो सरकार से प्रतिबध्य कर्मचारी आम जनता पर हुकूमत बनाये रखने के लिये चाहिये थे वे उन्हे उनकी सेवाओ को पक्का करके व मकान आदि की अतिरिक्त सुविधायें देकर मिले थे परन्तु अब हम स्वतंत्र हैं और एक की जगह पांच आदमी काम करने के लिये मिल सकते हैं तो इस परम्परा की क्या जरुरत है । दूसरे किसी सम्पन्न देश मे एसा नही हैं कि सरकारी कर्मचारी को इतनी सुविधायें दी जायें जो वहाँ के नागरिकों को भी नहीं मिलती हैं । अमेरिका मे किसी कर्मचारी को बिजली, पानी, मकान, फोन आदि मुफ्त नहीं मिलता । सिर्फ राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को बिजली, पानी, मकान, फोन, नौकर, खाना इत्यादि मिलते हैं, यूरोप मे भी एसा ही है ।और जितनी जगह इन्होंने कौलोनी बनायीं वहाँ पर भी भारत जैसा ही हाल है । क्या ये रिश्वत का ही दूसरा रूप नहीं है कि नेता खुद भी ये सेवायें लेते रहे हैं और जो उनसे रोजमर्रा के काम लिये जुडे हैं उन्हे भी वह सब देते हैं ? नतीजा, दो करोड़ सरकारी कर्मचारी व नेता 70% खर्चा अपने ऊपर कर लेते हैं और 98% जनता के लिये सिर्फ 30% संसाधन ही बचते हैं, वह भी, जो जनता स्थानीय राजधानियों मे रहती है अधिकतर उन्ही के रख रखाव मे , आम जनता जो 70%

है जो इन बड़े शहरो में नहीं रहती उसके लिये तो 10% भी नहीं बचता है । हम कम्युनिस्टों की तरह बात नहीं कर रहे हैं कि सबको बराबर मिले पर कम से कम इतना अन्धेर भी न हो कि नीचे वालों को उन्नति तक का अवसर न मिले ।
NGO यानि गैर सरकारी संस्थानो के नाम मे भी सरकारी शब्द क्यों ? क्योंकि सरकार शब्द मान्यता प्राप्त है यह हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है । इनका सही नाम सहकारी संस्थान होना चाहिये ताकि सहकारिता को बल मिले न कि सरकारिता के विरोध को । मै सरकारी तंत्र के समुचित संचालन व रख रखाव पर होने वाले खर्च मे कटौती की बात नहीं कर रहा हूँ ना ही सरकारी कर्मचारियों की तनखा को कम करने की बात कर रहा हूँ वरन फिजूल खर्ची को रोकने की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । बहुत से एसे विभाग हैं जिनकी जरुरत नहीं है पर चल रहे हैं, जैसे - विस्थापित राशन सप्लाई, सरकारी बिजली, पानी, सफाई, स्कूल, हस्पताल, प्रान्तीय पुलिस, इन सबके विभाग क्या जरुरी हैं ? डी एम, कमिशनर, गर्वनर क्या जरुरी हैं ? तंत्र मे मूलचूल परिर्वतन किये बिना और मौलिक प्रश्न पूछे बिना हम देश को उन्नति के कगार पर नहीं ला सकते हैं । लोगो में आपस में एकता और हमारे तंत्र की कमियों की समझ होगी तभी अच्छे कार्यकर्ता मिलेगें, जनता बटी होगी तो उसे राज्य करने वाले ही मिलेगें और शोषण होगा ।
आइये अब देखे हम भारतीये कैसे बटे हुये हैं । भाषाओं व प्रान्तों के आधार पर, प्रान्तों मे जाति के आधार पर, कार्यक्षेत्र मे उम्र व योनि के आधार पर व पूरे देश में धर्म के आधार पर मन्दिरों मस्जिदों, चर्चो व गुरुव्दारों मे बटे हुए हैं जबकि भगवान एक हैं, उनकी पूजाविधि में अंतर हो सकता है परन्तु इस बांट व अलगाव का लाभ हमारे तंत्र के नेता व अधिकारी उठाते हैं । इसके अलावा गरीब अमीर का अन्तर तो सर्वव्यापी है ही ।

राष्ट्र की एकता के दूरदर्शी लाभ को न समझ पाने के कारण जनता व्दारा एकजुट हो मांग को न करना या अपेक्षा का न होना निराशाजनक परिणामो को जन्म देता है और फिर निराशा की इस खाई से पढ़े लिखे समर्थ व्यक्तियों तक को हमने यह कहते सुना है- कि जी इस देश में कुछ सुधार नही हो सकता है । जो ईमानदार है उनकी आवाज मे आवज मिलाकर हम उसे सबल नहीं बनाते, नतीजा यह है कि हर आदमी अकेला है और डर से अभिभूत है सिर्फ किनारे पर खडे होकर दर्शक की स्थिति मे बेबस जी रहा है ।

यह सही है कि जीवट वाले इक्के दुक्के लोग जो जी जान से प्रयास कर रहे है उसके परिणाम स्वरुप धीरे धीरे कुछ जगह जो सुधार हो रहा है वह टिमटिमाते दिये की लौ के समान प्रकाश दे रहा है । यह प्रकाश सूर्य की तरह पूरे देश को तभी लाभ दे सकता है जब हम लगन के साथ, जो हमे गलत लगता है उसे हटाने के लिये जनमत को साथ लेकर अपने को सबल बनाते हुए, तंत्र को अस्पष्टता से स्पष्टता, भारीपन से हल्के की ओर ले जाते हुए सरल बनायें। हमे एसा तंत्र चाहिये जिसमे प्रोत्साहन की झलक हो,जो साधारण से साधारण आम आदमी को सरलता से समझ मे आ जाये । फिर उस तंत्र को अपना पूर्ण सहयोग देकर सफल बनायें । इस पर हम सब एक मत हो सकते हैं चाहे प्रर्दशनो के जरिये या आम सभाओं के जरिये जनमत सबल बनाया जा सकता है क्योंकि सारी जनता की जरुरतें व समस्याएँ तो एक ही हैं न ? यही एकता का आधार हैं - रोटी, कपड़ा और मकान, पानी, बिजली सबको चाहिये । TV, रेडियो, फोन, कम्प्यूटर आदि सुविधाओ की अभिलाषा सभी को है और अपनी अपनी मातृभाषा मे है पर एकता, राष्ट्रभाषा को प्रतिष्ठित करके उसे सीखने व प्रयोग करने मे हैं । नियम सबके लिये एक होने चाहिये । प्राकृतिक विपदाओं से तकलीफ सबको एक सी होती है। नियम इतने सरल हों कि जहाँ से भी जिसकी भी माँग आए तबाही से उबरने के लिये सबको बराबरी का मान, व्यवहार व मदद मिले, मजदूर हो या नेता, जनता हो या जनता का कर्मचारी । जनता फाके करे और जनता सेवक मक्खन खाये एसा तंत्र नहीं चाहिये । देश की सुरक्षा का भार केवल सरकार का ही नहीं वरन प्रत्येक व्यक्ति पर भी होना चाहिये,चाहे कारण आन्तरिक हो या बाहरी, इसमे जनता तंत्र की सहयोगी बने । हर उस नियम का पालन करना होगा जिन्हें जनता का अनुमोदन प्राप्त होगा ये नियम देश, काल, पात्र और धर्म की सीमा से परे होगें ।

जनता को नेता चुनने का अधिकार है पर हमारे सविधान मे कसौटी पर खरे न उतरने की दशा मे जनता को उसे हटाने का प्राविधान नहीं है । सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पक्की है। संविधान के अन्तरगत चाहे जरुरत हो या नहीं और किसीको अपने काम को निपुणता से न करने पर भी, इन्हें हटाना मुश्किल ही नहीं वरन असम्भव है। न्यायाधीश,पुलिस आदि को भी यही संरक्षण प्राप्त है, स्थानीय जनता को न तो इनकी नियुक्ति ना ही हटाने का अधिकार है। सरकार के निर्णय को मानना ही जनता की नियति है। परिणाम स्वरुप आज स्थिति यह है कि उपर से थोपे नियमों को लागू करवाना सरकार के बस की बात नहीं, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही क्यों न हो । जनता बाध्य है बोझ ढोने के लिये, अगर पास मे रिश्वत देने को धन नही हैं तो गल्ती से समझौता करो । प्रजातंत्र मे एसा नही होना चाहिये। यदि कोई जनता सेवक अपना काम योग्यता पूर्वक नहीं कर रहा हो तो उसका स्थनांतरण क्यों ? किसी और स्थान की जनता एसे सेवक का क्या करेगी ? क्यों उसकी अयोग्यता व बेईमानी अनजान जनता पर थोपी जाय ? स्थानातरंण बन्द करो और एकता पूर्वक स्पष्ट जानकारी की माँग करो। यह सब अब संभव है - RTI 2005 बिल के अन्तर्गत। जनता-सेवकों की तीन गल्तियाँ माफ उसके बाद निलम्बन। हमारी तंत्र प्रणाली के आधार हों - न्याय, प्रोत्साहन, विश्वास, स्पष्टता व सत्ता का विकेन्द्रीकरण । लोगो को बांटने के बजाय सरकार के कामो को बांटा जाय।

1. एक स्वायत्त संस्था नियमो को बनाये व जांचे- बैधानिक
2. दूसरी स्वायत्त संस्था नियमो को लागू करे - प्रशासनिक
3. तीसरी स्वायत्त संस्था यह व्याख्या करे कि नियमो का पालन सुचारु रुप से हो रहा है या अन्यायपूर्वक हो रहा है - न्यायिक

इन तीनो संस्थानो का चयन जनता के बहुमत के आधार पर हो । इन सबमे आपस मे एकता जनता के शोषण के लिये नहीं वरन जनता के हेतु हो व आपस मे जबाबदेही हो ।

4. देश की सुरक्षा के लिये सेना (वायु, थल, जल), केन्द्रीय व स्थानीय सुरक्षा के लिये पुलिस स्थानीय हो जिसे स्थानीय जनता का पूर्ण समर्थन उसके प्रतिनिधियों के जरिये प्राप्त हो ।
5. जनतंत्र मे जनता-चयनित व्यक्ति मानोनीत सेवको से अधिक प्रभावशाली हो। अगर तंत्र प्रणाली के नियम दमदार हों तो अधिकारी कोई भी ईमानदार व्यक्ति हो सकता है, आवश्यकता है अच्छे चयन व प्रशिक्षण की।
6. देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा केन्द्रीय हो ।
7. देश की कर व्यवस्था का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये। आय पर स्थानीय, प्रान्तीय व केन्द्रीय कर 2%, 5%, 15% होना चाहिये। फिर भी केन्द्र प्रान्तों व स्थानीय संस्थानो को विशेष कार्यों के लिये आर्थिक सहायता दे । गांव का लगान गांव पंचायत के पास ही रहना चाहिये ।
8. मकानो पर कर सामयिक मूल्यों पर आधरित हो न कि जब मकान का निर्माण हुआ था । तभी सेवायें भी समायिक मूल्यों के आधार पर मिल सकेंगी।
9. पानी, बिजली आदि की जरुरतें, स्थानीय स्तर पर सर्वमान्य स्थानीय कम्पनियों के जरिये, जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से पूरी हों।
10. फोन सेवा स्थानीय हो सकती है पर देश व्यापी आधार होना चाहिये प्रान्तो के आधार पर नहीं, मोबाईल फोन पर रोमिंग का क्या मतलब है ? पूरे देश मे एक ही दर प्रतिकौल हो तो सरलता होगी ।
11. सेल्फ हेल्प ग्रुप या सहयोगी स्वयं सेवी वर्ग को बढ़ावा दिया जाय ।
12. चाहे हम कितने भी बटे हो पर एसा कुछ न करें जिससे देश का, प्रान्त का, शहर, गाँव या किसी व्यक्ति का अहित हो। हम जीतें हमारा गाँव, शहर, प्रान्त, व देश सभी विजयी हों । विजय विजय विजय ही सबकी हो तभी हम जीतते हैं तो किसी का हारना जरुरी नहीं होता है, इस तरह हम सब आगे बढेंगे।
13. नियम सरल हों ताकि आम जनता उनका अनुसरण कर सके या उनका मूल्यांकन व बदलाव आवश्यक हो तो उस दिशा मे कदम उठाने का जनता के पास कोई रास्ता होना चाहिये ।
14. एक अच्छे प्रजातंत्र मे हर नियम की जांच हो तब ही अनुपयोगी ब उन्नति मे बाधक नियमो का उन्मूलन हो पायेगा । किसी भी चयनित पद पर नियुक्ति दो बार की अधिकतम अवधि तक सीमित हो ।

15. योजनाएँ नीचे से स्थानीय अवयवों की आवश्यकता के आधार पर बने और स्थानीय संसाधनो पर मुख्य रुप से आधरित हो न कि दिल्ली मे बैठे योजना आयोग के अनुमानो पर ।
16. अपनी जरुरतों की पूर्ति स्थानीय संसाधनो पर मूख्य रुप से आधारित होनी चाहिये न कि बाहर से आयातित संसाधानो पर, तभी स्थानीय सम्पन्नता संभव होगी । गांव वाले अपना व्यापार अपने पास के गांव मे करेगें तभी गांव सम्पन्न होंगे । यह सत्य है कि आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है परन्तु इच्छाओं की पूर्ति पूर्ण रुप से कभी नहीं होती, पर वह गरीबी नहीं है ।

एक बात हम सदा याद रखें कि भारत मे हमे प्राकृतिक सम्पदायें बहुलता से प्राप्त हैं अतः हम भाग्यवान हैं लेकिन आलसी व मूर्ख न बने और जल, वायु, पृथ्वी तथा सूर्य की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें ताकि हम प्रकृति के साथ सम्पन्न रह पायें । एकता के होते शोषण नहीं पनप सकता है, जरा विचार करें तो स्पष्ट हो जायेगा । जन-एकता होगी तो भ्रष्टाचार और अन्याय के विरूध्द आवाज उठेगी। जाति एकता दूसरों को डराने के लिये नहीं बल्कि अपनी जाति मे एक दूसरे को ऊपर उठाने मे सहायक होनी चाहिये । किसी जाति का गौरव यही है कि हम दूसरी जाति की इज्जत करें और उनके साथ सहयोग से रहना सीखें । वास्तव में पूरी मानव जाति ही बस एक जाति है और हमारा गौरव सम्पूर्ण देश की उन्नत्ति मे कन्धा मिलाकर सबका हाथ बटाने मे है । एकता हमारे समय की माँग है। हमे जातीय एकता एक दूसरे को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिये चाहिये । प्रांतीय व भाषाई एकता की वोटों की राजनीति मे भी जरुरत है, सभी भाषायें आपस मे बहने हैं । जब हमारी सरकार अल्पमत की होगी तो विपक्षी अधिक होंगे और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना आसान नहीं होगा ना ही बहुजन हिताय होगा । चूनाव पूर्ण होते ही सबको एक होकर देश-हित मे कार्य करना चाहिये । हमारे प्रधान मंत्री किसी एक पार्टी के होकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व केसै कर पायेंगे ? सफल शासन के लिये उन्हें जनता व कर्मचारियों की एकता की जरुरत होगी । हमे सहयोग के जरिये उनके हाथ मजबूत करने चाहिये ताकि वे जन-हित व देश-हित मे कार्य सुचारु रुप से कर सकें । निर्णय पर पहुँचने से पहले हम अलग-अलग हो सकते हैं पर निर्णय लेने के लिये हमारी एकता जरुरी है।

एक बात सदा याद रक्खें कि किसी न किसी योजना, जिसे सरकार व जनता का बहुमतीय समर्थन प्राप्त हो, का हेतु बने । हो सके तो यथा सम्भव सहायता दें वरना रास्ते मे रोड़े न अटकायें । आशा है आप इस लेख को पढ़कर मुझसे सहमत होगें कि एकता का बल आज की शोषण जानित निर्बलता, असहायता व दयनीयता से जनता को उबार सकता है । हमे एक होकर देखना यह है कि हमारे देश की योजनाएँ, स्थानीय संसाधनो के अनुरुप व बहुजन हिताय हों और उनसे एक वर्ग के व्दारा दूसरे वर्ग का शोषण न हो, जैसा आजकल की ज्यादातर योजनाओं में प्रत्यक्ष दिखाई देता है । योजनाएँ जब बहुजन हिताय होंगी तो बहुमत उनके साथ होगा और कोई शोषित नहीं होगा ।

रश्मि उमेश रोहतगी 24161 Nilan Drive Novi MI 48375 USA (248) 471-5786
webpage :"www.rurohatgi.com" email:rurohatgi@yahoo.com